भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 362

जिसका उत्तर 27 नवंबर, 2024 को दिया जाना है ।

6 अग्रहायण , 1946 (शक)

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान

362. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) पर कुल कितनी धनराशि स्वीकृत, आवंटित और व्यय की गई;

(ख) वैश्विक महामारी के दौरान कई केंद्रीय/राज्य योजनाओं के कारण डिजिटलीकरण में आई तेजी के बावजूद पीएमजीदिशा को कम और/या बंद किए गए आवंटन के क्या कारण हैं;

(ग) पीएमजीदिशा के तहत प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और क्या मानक तय किए गए हैं;

(घ) क्या उक्त अभियान के संबंध में कोई प्रभाव मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) देश भर में वर्तमान में संचालित पीएमजीदिशा केंद्रों की संख्या का गांव-वार ब्यौरा क्या है;

(च) कोविड-19 वैश्विक महांमारी के मद्देनजर आयोजित की गई कक्षाओं का ब्यौरा क्या है और क्या इन केंद्रों पर नियमित प्रशिक्षण फिर से शुरू करने के लिए कोई नवाचार हैं; और

(छ) इस अभियान के प्रमाणित लाभार्थियों को गारंटीकृत रोजगार अवसरों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (छ): ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश भर में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) तक पहुंच स्थापित करना था।

यह योजना कोविड-19 महामारी के दौरान भी संबंधित केंद्रीय/राज्य/जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/निर्देशों में दी गई छूट का पालन करते हुए क्रमबद्ध तरीके से जारी रही। पीएमजीदिशा योजना के तहत प्रशिक्षण की गुणवत्ता को निम्नलिखित उपायों के माध्यम से सभी प्रशिक्षण केंद्रों/सीएससी में उद्देश्यों के अनुरूप बनाए रखा गया:

- सभी प्रशिक्षण केंद्रों/सीएससी में सभी अभ्यर्थियों के लिए मल्टीमॉडल प्रारूप में 22 भाषाओं में मानकीकृत मल्टीमीडिया सामग्री के साथ प्रशिक्षण प्रदान किया गया;
- कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुरूप मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) बनाई गईं और प्रशिक्षण और परीक्षा के लिए सभी प्रशिक्षण केंद्रों के साथ साझा की गईं;

- प्रशिक्षण केंद्रों को अपनी गतिविधियां फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित करने हेतु उनके साथ वर्चुअल सत्र और कार्यशालाएं आयोजित की गईं;
- पंजीकृत/प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जो प्रशिक्षण और/या प्रमाणन के लिए उपस्थित होने में असमर्थ थे;
- पीएमजीदिशा पोर्टल पर बुनियादी जानकारी के साथ एक चैटबॉट बनाया गया था जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया गया था;
- प्रशिक्षण केंद्रों को लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर समूहों में शामिल होने और इन समूहों के माध्यम से प्रासंगिक प्रशिक्षण सामग्री साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया;
- पीएमजीदिशा सामग्री को डिजीशाला चैनल पर अपलोड किया गया, ताकि उम्मीदवार स्वयं इसका संदर्भ ले सकें और मामूली प्रशिक्षण/संशोधन के बाद पंजीकरण और मूल्यांकन के लिए तैयार हो सकें।

वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान योजना के लिए उपयोग की गई कुल धनराशि क्रमशः 300.00 करोड़ रुपए, 250.00 करोड़ रुपए और 165.92 करोड़ रुपए थी।

पीएमजीदिशा योजना का प्रभाव विश्लेषण तीन एजेंसियों अर्थात् आईआईटी दिल्ली, सामाजिक विकास परिषद (सीएसडी) और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा आयोजित किया गया था। पीएमजीदिशा योजना का नवीनतम प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन आईआईपीए द्वारा किया गया था। मूल्यांकन रिपोर्ट का सार यह है कि पीएमजीदिशा अपने बड़े पैमाने और दूर से संचालित परीक्षाओं के उपयोग के कारण एक अनूठी योजना है। पीएमजीदिशा के तहत प्रदान किए गए प्रशिक्षण का सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और डिजिटल मीडिया के अन्य रूपों को अपनाने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इसने अपने प्रतिभागियों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए सूचना और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक उनकी पहुँच को सक्षम करके लाभान्वित किया है, जिससे देश में समग्र डिजिटल विभाजन को कम करने में मदद मिली है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीएसपी) में 18%, जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के लिए 12% और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए 11% निधि का उपयोग करके संवेदनशील वर्गों का सशक्तिकरण सुनिश्चित किया गया है।
- महिलाओं की भागीदारी बहुत बड़ी है और ग्रामीण स्तर पर उनके समावेश से पूरे परिवार के लिए सीखने का रास्ता खुलेगा।
- 55% से अधिक प्रतिवादियों ने पीएमजीदिशा प्रशिक्षण के बाद अपनी आजीविका में प्रत्यक्ष लाभ का हवाला दिया।
- लगभग 50% प्रतिवादियों ने बताया कि पीएमजीदिशा ने उन्हें बेहतर रोजगार पाने में मदद की।

इसके अलावा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने अपने 79वें दौरे (जुलाई, 2022 से जून, 2023) में 'व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण' (सीएएमएस) आयोजित किया और उनकी रिपोर्ट के आंकड़ों ने भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रवृत्ति का संकेत दिया। 31 मार्च, 2024 तक देश भर में 6 करोड़ के मुकाबले 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, यह योजना समाप्त हो गई है। उपरोक्त रिपोर्टों से और ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन के उपयोग, इंटरनेट की पहुंच और डिजिटल जुड़ाव में उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए, योजना के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया है।

****